

संपादकीया

रोजगार के आदर्श बदलें

बेरोजगारी की चीखों के बीच नीतियों का इंतजाखाल करना भी मुश्किल हो गया है। सरकार गेस्ट टीचर के लिए स्कूलों के गेट नहीं खोल पाई तो इसलिए इस नीति की घोषणा ने युवाओं के सुर बिगाड़ दिए। कुछ इसी तरह जेओप-817 की परीक्षा पर तरस खाने का मुद्दा भी रहा। जिस परीक्षा प्रणाली के भ्रष्ट तंत्र ने हमीरपुर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उखाड़ फेका, उसी के तहत हुई जेओप-ए परीक्षा को बचाने का प्रयास जारी है। ये परीक्षार्थी अब फरियादी हैं, तो सरकार की अदालत बदल रही है। जाहिर है बेरोजगारी की चीखों की सत्ता अनन्दखी नहीं कर सकती, लेकिन मंत्रिमंडल के बीच नैतिकता का विभाजन स्पष्ट रहा। अब मुख्यमंत्री जेओप-ए परीक्षा को तमाम संशय से दूर रखते हुए नौकरी के आवरण से ढापना चाहते हैं। बहरहाल मसला सरकारी नौकरी को लेकर पुणः खिदमत कर रहा है, तो आंसू पॉंड्सने के लिए मुख्यमंत्री के मुलायम हाथ स्पर्श कर रहे हैं। रोजगार के बाजार में सरकार की आस्था सदा बदलती रही है और यही वर्तमान सरकार की परीक्षा और गारंटी है। एक लाख नौकरियों की बिसात पर अब कुछ ऐसे ही टोटके काम आएंगे। जाहिर है जेओप-ए परीक्षा अगर बरी हो जाए, तो सरकारी रोजगार के आंकड़े कुछ तो काम आएंगे। नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का अंतर आज तक हिमाचल की नीतियों को समझा नहीं आया। हालांकि स्टार्टअप के जरिए वर्तमान सरकार की ग्रीन नीति रोजगार के अवसर सुजित करने को तत्पर है या पर्यटन के जरिए सरकार रोजगार को स्वरोजगार का पथगच्छ सौंपना चाहती है।

देश के प्रथम 'परमवीर चक्र' विजेता हिमाचल प्रदेश के मेजर 'सोमनाथ शर्मा' के भाई जनरल 'वीएन शर्मा' ने 1988 में भारतीय थलसेना के प्रमुख उस वक्त श्रीलंका के आतंकी समूह 'पीपल लिबरेशन ऑफ टमिल इलम' के लड़ाकों ने पर्टटों का भेष धारण करके समंदर में बसे देश मालादीप पर हमला करके वहां तखापलट को अंजाम दे दिया था।

सरकार गेस्ट टीचर के लिए स्कूलों के गेट नहीं खोल पाई तो इसलिए कि इस नीति की घोषणा ने युवाओं के सुर बिगाड़ दिए। कुछ इसी तरह जेओए-817 की परीक्षा पर तरस खाने का मुद्दा भी रहा। जिस परीक्षा प्रणाली के भ्रष्ट तंत्र ने हमीरपुर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उखाड़ फेंका, उसी के तहत हुई जेओए परीक्षा को बचाने का प्रयास जारी है। ये परीक्षार्थी अब फरियादी हैं, तो सरकार की अदालत बदल रही है। जाहिर है बेरोजगारी की चीखों की सत्ता अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन मत्रिमंडल के बीच नैतिकता का विभाजन स्पष्ट रहा। अब मुख्यमंत्री जेओए परीक्षा को तमाम संशय से दूर रखते हुए नौकरी के आवरण से ढापना चाहते हैं। बहरहाल मसला सरकारी नौकरी को लेकर पुनः खिदमत कर रहा है, तो आंसू पौछने के लिए मुख्यमंत्री के मुलायम हाथ सर्प्श कर रहे हैं। रोजगार के बाजार में सरकार की आस्था सदा बदलती रही है और यही वर्तमान सरकार की परीक्षा और गरंटी है। एक लाख नौकरियों की बिसात पर अब कुछ ऐसी ही टोटके काम आएंगे। जाहिर है जेओए परीक्षा अगर बरी हो जाए, तो सरकारी रोजगार के अंकड़े कुछ तो काम आएंगे।

मुजरिम बन गई। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेकर ही अगर बीबीएन में एक राज्यस्तरीय संस्थान पैदा करते, तो काम करने का कोड बदल जाता। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने फिल्म शूटिंग को सरल बनाने के लिए एक वांछित घोषणा करके सिनेपर्टन के उद्दम को टटोला है। अगर हिमाचल सिनेमा उद्योग से पीपों बढ़ा ले। गरली-परागपुर में फिल्म सिटी की अवधारणा में अधोसंरचना तथा एक राज्य स्तरीय फिल्म एवं टीवी प्रशिक्षण कालेज शुरू कर दे, तो रोजगार से रोजेन्यू के उद्धार निकलेंगे। हिमाचल की प्रतिभा से निकल रहे स्वरोजगार की पहचान की जाए, तथा इसे उचित अवसर दिए जाएं तो रोजगार के मायने बदलेंगे। इसके लिए प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मेलों को सर्वप्रथम एक मेला विकास प्राधिकरण के तहत लाना होगा। रोजगार को सरकारी नौकरी से हटाकर अगर परिभाषित नहीं किया गया, तो यही रोजगार के उपनाम बदलकर 'गेस्ट फैकल्टी' जैसे मुहावरों पर शक रहेगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने के फलक पर प्रोत्साहन बढ़ा कर सरकार को नौकरी की पुरानी मान्यताएं तोड़ी होंगी।

Page 1

चाने के लिए अमरीका, ब्रिटेन व मलेशिया जैसे कई देशों से मदद की गुहार लगाई

भारत का एहसान भूल रहा मालदीव

‘आपरेशन कैवटस’ भारतीय सेना की दास्तान-ए-शजात की

वो जांबाजी जब हिंदौस्तान के रणबांकुरों ने जीखिम भरे सैन्य आपरेशन को अंजाम देकर मालदीव को आंतकियों से मुक्त कराया था। देश के प्रथम 'परमवीर चक्र' विजेता हिमाचल प्रदेश के मेजर 'सोमनाथ शर्मा' के भाई जनरल 'वीएन शर्मा' सन्-1988 में भारतीय थलसेना के प्रमुख थे। उस वक्त श्रीलंका के आंतकी समूह 'पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम' के लड़ाकों ने पर्यटकों का भेष धारण करके समंदर में बसे देश मालदीव पर हमला करके वहां तख्तापलट को अंजाम दे दिया था। आंतकियों के घेरे में फंस चुके मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति 'मौमून अब्दुल गयूम' ने अपने मुल्क को उस आंतकी हमले से बचाने के लिए अमरीका, ब्रिटेन व मलेशिया जैसे कई देशों से मदद की गुहार लगाई, मगर मालदीव के एयरपोर्ट, टीवी टावर व रेडियो स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर चुके आंतकियों का मुकाबला करने की जहमत किसी भी मुल्क ने नहीं उठाई थी। आंतकियों के तर्जुमान पाकिस्तान से भी मालदीव ने मदद के लिए राष्ट्रा किया था, मगर निराशा हाथ लगी। जब अब्दुल गयूम के लिए सबाल मालदीव की इज्जत-ए-नफज का बना, तब ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री 'मारग्रेट थैचर' ने मालदीव को भारत से मदद मांगने का मशविरा दे डाला था। आखिर मालदीव के सदर मौमून अब्दुल गयूम की गुजारिश पर भारत की तत्कालीन हुक्मत व भारतीय सेना हरकत में आई। मालदीव को उस आंतकी हमले से आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने 'आपरेशन कैक्टस' लांच किया। सेना की 50वीं 'पैराशूट ब्रिगेड' व 'छह पैराशूट' यूनिट तथा '17वीं पैराशूट फ़िल्ड रेजिमेंट' के जवान ब्रिगेडियर 'फारूक बुलसारा' की कमान में तीन नवंबर 1988 की रात को मालदीव के 'हुलहुले' एयरपोर्ट पर उतरे तथा समुद्री रास्ते से मालदीव की राजधानी 'माले' पहुंचे। भीषण गोलीबारी में 19 आंतकियों को हलाक करके भारतीय कमांडोज ने मालदीव में आंतकी तख्तापलट की मंसूबाबंदी को नाकाम करके राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम व उपरक्षामंत्री 'इल्यास इब्राहिम' सहित कई लोगों को 18 घंटों के

An aerial photograph of a tropical island resort. The island features a dense forest of palm trees and lush greenery. A large, clear blue lagoon surrounds the island, with several overwater bungalows built on stilts extending into the water. A paved walkway leads from the main area of the island to one of the bungalows. The sky is bright and clear.

योग दिवस के मौके पर माले के फुटबाल मैदान में योग कर रहे भारतीय मूल के लोगों पर भीड़ ने मजहबी आक्रोश में आकर हमला कर दिया था। सात जनवरी 2023 को मालदीव की सरकार के तीन वज़ीरों ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हालांकि मालदीव जल्द ही घुटनों के बल पर आ गया और अपने उन वज़ीरों को निलंबित कर दिया। बर्तानिया हुक्मत की गुलामी से जुलाई 1965 में आजाद हुए मालदीव को आजाद मुल्क का दर्जा देने वाले देशों में भारत अग्रणी था। मालदीव की सेना 'मालदीवियन नेशनल डिफेस फोर्स' की ट्रेनिंग कई वर्षों से भारतीय सेना ही करवाती है। सन् 2004 में मालदीव में विनाशकारी सुनामी के बाद वहां मदद भेजने में भी भारत ने पहल की थी। सन् 2014 में मालदीव का 'वाटर ट्रीटमेंट' आग लगने से खाक हो गया था। पेयजल के संकट से जूझ रहे मालदीव की आवाम को भारत ने आपरेशन 'नीर' चलाकर पेयजल की आपूर्ति की थी। सन् 2010 व 2013 में भारत ने मालदीव को दो हैलिकॉप्टर तथा सन् 2020 में एक विमान भी तोहफे में दिया था। मालदीव की राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने के लिए भारत के कुछ सैनिक वहां रहते हैं। भारत के उन 88 सैनिकों को राष्ट्रपति मुहिज्जु 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का फरमान जारी कर चुके हैं। हमारे देश के हुक्मरानों को मालदीव की इस कारकर्दगी पर संज्ञान लेना होगा। 'इंडिया आउट' का नारा देकर मालदीव की हुक्मत पर काबिज होने वाले मो. मुहिज्जु की ड्रैगन संग रफाकत मालदीव को महंगी साबित होगी, क्योंकि चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में मालदीव भी शामिल है। बहरहाल चीन की उल्फत में छूब कर भारत के विरोध में उतरे मालदीव के एहसान फरामोश हुक्मरानों को भारतीय सेना के उन शूरवीर पैरा कमांडोज व नौसेना तथा वायुसेना का मरहून-ए-मिन्नत रहना होगा जिन्होंने सन् 1988 में मालदीव में तख्तापलट के मूसूबों को ध्वस्त करके वहां जम्हूरियत को दोबारा कायम कर दिया था। आपरेशन कैट्स को अंजाम देकर भारतीय कमांडोज ने दुनिया को एहसास करा दिया था कि विश्व की बेहतरीन स्पेशल फोर्स भारत के पास हैं। यह देश के लिए गर्व की बात है।

चुनावी साल में अंतरिम बजट से उम्मीदें

एक फरवरी का वित्तमंत्री नामला सातारामण के द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने वाले वर्ष 2024 के अंतरिम बजट की तैयारियों का अंतिम चरण 24 जनवरी को हलवा वितरण समारोह के साथ आरंभ हुआ। पिछले तीन पूर्ण बजट की तरह नया अंतरिम बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वस्तुतः इस समय पूरे देश की निर्गाहें वित्तमंत्री के द्वारा पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट की ओर लगी हुई हैं। वस्तुतः देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उस वर्ष दो बजट आते हैं। एक अंतरिम बजट और दूसरा पूर्ण बजट होता है। सामान्यतया अंतरिम बजट में नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य होता है। लेकिन अधिकांश अंतरिम बजटों में लोक लुभावन योजनाओं और बड़ी-बड़ी राहतों का ढेर लगाया जाता रहा है। इस बार वित्तमंत्री सीतारामण वित्तीय अनुशासन के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के महेनजर जरूरी राहतों और आर्थिक कल्याण की योजनाओं से संतुलित अंतरिम बजट पेश करते हुए दिखाई दे सकती है। निःसंदेह इस समय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को अंतिम रूप देते समय दो अहम मसले वित्तमंत्री के समझ हैं। एक का संबंध उस राजकोषीय गुंजाइश और आकार से है जो फिलहाल केंद्र सरकार के पास अनुकूल स्थिति में है और दूसरा मुद्दा आगामी आम चुनावों में आवश्यक चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कुछ नई व्यय योजना की घोषणा

पिछले आठ वर्षों में आयकर रिटैन भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छालांगे लगाकर वुड्डी हुई है। 2023-24 के 31 दिसंबर तक आयकर रिटैन रिकॉर्ड 8.18 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। जहां पिछले आठ वर्षों में आयकर रिटैन भरने वाले दोगुने हुए हैं, वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। वित्त वर्ष 2014-22 के दौरान व्यक्तिगत आय असमानता 0.472 प्रतिशत से घटकर 0.402 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान 3.5 लाख रुपए के कम आय वाले समूह से 36.3 फीसदी लोग उच्च आय वाले समूह में शामिल हो गए हैं। निःसंदेह वित्तमंत्री के मुद्रियों में देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वुड्डी की बड़ी अनुकूलताएं हैं। इसके अलावा वित्तमंत्री के पास कुछ और अनुकूलताएं भी हैं, जिनके मद्देनजर वे उपयुक्त जरूरी राहत दे सकती हैं। इस वित्त वर्ष 2023-24 में वित्तमंत्री सीतारमण वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए वे अब तक राजकोषीय घाटे को बजट लक्ष्य के मुताबिक जीडीपी के 5.9 तक नियंत्रित रखते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ी हैं। यह बात भी स्पष्ट रूप से उभरकर दिखाई दे रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले 2019 के अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि व आयकर राहत देने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए थे। चूंकि पिछले माह दिसंबर में राज्यों के उत्साहजनक चुनावी नीतियों

ल्याणिकरा योजनाओं का भूमिका अहम माना गइ ह, इस में खट्टे हुए वितर्मंत्री आमजन के हितार्थ कुछ महत्वपूर्ण जिक और आर्थिक कल्याण की योजनाओं के साथ-साथ आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जरूरी प्रावधान कर सकती है। नए अंतरिम बजट में छोटे करदाताओं व मध्यम वर्ग को कुछ राहत दी जा सकती है। में किफायती आवासों के लान पर ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करती है। नई मैन्युचरिंग यूनिट के लिए आयकर छूट की बड़े सकती है। किसानों और महिलाओं के लिए अंतरिम में बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जानी है। नए बजट में राजकोषीय घाटा और विनिवेश कम हो सकता है। विनिवेश लक्ष्य 50 हजार करोड़ रुपए चे रखा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एसएमई को प्रोत्साहनमूलक राहत दी जा सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में योग्य करने के लिए सरकार नए अंतरिम बजट से पोलिलाई ना का दायरा बढ़ाते हुए इसे कपड़ा और हस्तशिल्प जैसे उत्कर्ष करत कर सकती है, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहनमूलक राहत दे सकती है। नए अंतरिम बजट में डिजिटल क्रांति को बढ़ाने से संबंधित मोबाइल सेवा आओं सहित विभिन्न उत्पादों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कंपनियों के लिए व्यापारिक व्यवहार को सही दिखाई दे सकते हैं।

सत्ता और सियासतः बिहार तो सिर्फ एक झलक है, इस 'अनैतिकता' की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर

नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से विपक्षी हड्डों के बीच जो अग्रजकता और दल कांग्रेस को दोषी ठहराने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी ग़ाहल के बफादार नेता ख़रगे को एक रपट भी थी, जो भाजपा ने कराया लोकसभा चानपां में भाजपा अपने सभी

जिसे अवसाद समझ रहे हैं वह बर्न आउट
तो नहीं, लेकिन दोनों में है बड़ा फर्क

A black and white photograph of a man sitting on a floor against a wall. He is wearing a light-colored t-shirt and dark trousers. His head is resting in his hands, and he appears to be in a state of distress or deep thought. The background is dark and out of focus.

म ऐसा नहीं हाता। अमेरिकी साइकिएट्रिक ऐसोसिएशन की डॉ रेबेका ब्रेंडल कहती है कि दोनों में मुख्य फर्क यह होता है कि जब आप काम से दूर होते हैं, तब बर्न-आउट खत्म होने लगता है, जबकि परिस्थितियां बदलने से अवसाद में कमी नहीं आती। अवसाद की वजहें आनुवंशिक हो सकती हैं या जीवन में किसी दर्दनाक घटना को सहने या फिर बड़े बदलाव से गुजरने वालों में अवसाद की समस्या हो सकती है। बर्न-आउट खुद भी अवसाद के लिए जमीन तैयार कर सकता है। डॉ गोल्ड के अनुसार, 'अवसाद हो या बर्न-आउट दोनों में फर्क जरूर है लेकिन किसी तरह का मूर्मेट दोनों स्थितियों में कारगर साबित हो सकता है। प्रकृति को निहारते हुए दस मिनट की वॉक (व्यायाम की तरह नहीं) से काफी फायदा मिल सकता है। कुछ समय के लिए खुद को मोबाइल स्क्रीन से दर रखने के भी जार्ड्झ नीति जी होते हैं।'

जून, 2023 से, जब 'इंडिया'
गठबंधन अस्तित्व में आया, कमेटी
राज, कई शक्ति केंद्र, एक ही पार्टी
को प्रमुखता और संवाद की कमी ने
इसका संकेत दे दिया था। यह सुनने
में भले अजीब लगे, लेकिन कुछ
अस्पष्ट कारणों से कांग्रेस ने अपने
ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगो
को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार
बनने या गठबंधन का अध्यक्ष बनने
से इन्कार कर दिया। इसने एक
क्षेत्रीय क्षत्रप को संयोजक के पद से
वंचित करने, गठबंधन सचिवालय
की स्थापना करने या नेतृत्व के मुद्दे
को निपटाने की संभावनाओं को

नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से विपक्षी दलों के बीच जो अराजकता और चैनी बढ़ी है, उसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं। बेशक नीतीश कुमार का पाला बदलना अनैतिक हो सकता है, तर कंग्रेस की अगुआई वाले 'इंडिया' गठबंधन ने इसे दल कंग्रेस को दोषी ठहराने की योजना बना रहे हैं। कंग्रेस के भीतर भी राहुल के वफादार नेता खरगे को दोषी ठहराने में रुचि रखते हैं, जबकि कांग्रेस के भीतर आम तौर पर लोग राहुल के खिलाफ हैं। प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति संकेत देती है कि 10 जनपथ के भीतर आवास में दुखी थी। वह असामन्य बैठक एक रपट भी थी, जो भाजपा ने कराया लोकसभा चुनाव में भाजपा, अपने समीक्षकों सकती है। सर्वे अव्योध्या राम मंदिर की सर्वे में यह भी सामने आया कि उसके 2019 में भाजपा ने जद-यू के साथ 4

नान दिया। जून, 2023 से, जब 'झड़िया' गठबंधन नस्तित्व में आया, कमटी राज, कई शक्ति केंद्र, एक ही पार्टी को प्रमुखता और संचावद की कमी ने इसका संकेत दिया था। यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन कुछ ऐस्पष्ट कारणों से कांग्रेस ने अपने ही पार्टी अध्यक्ष लिल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने या गठबंधन का प्रध्यक्ष बनने से इन्कार कर दिया। इसने एक नीतीय क्षत्रप को संयोजक पद से वंचित करने, गठबंधन सचिवालय की वापाना करने या नेतृत्व के लिए दुहों को निपटाने की भावनाओं को खत्म कर दिया। इस तरह से, इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी पूरी तरह कांग्रेस और गांधी परिवार की है, खासकर राहुल गांधी की, जिन्होंने सीट समाचोरण के लिए गठबंधन में आम सहमति बनाने के बाजाय न्याय यात्रा को चुना। गांधी परिवार को अफसोस हो रहा होगा कि कैसे उन्होंने नीतीश को 'झड़िया' गठबंधन का संयोजक बनाकर अंत करने का सुनहरा मौका गंवा दिया। सभी लोग जब नीतीश को संयोजक बनाने पर सहमत हो गए थे, तब राहुल ने कथित तौर पर तर्क दिया कि चूंकि ममता नर्जी नहीं थीं, इसलिए उनकी सहमति ली जानी चाहिए। अगले दो सप्ताह तक राहुल इसे या तो भूल गए या नजर अंदाज करने का फैसला लिया। ममता के साथ गोई बातचीत नहीं हुई, अंततः निराश नीतीश ने भाजपा का साथ मिलने का फैसला किया। भाजपा की रणनीति 2024 के चुनाव में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने से ज्यादा विपक्षी गठबंधन को लोकसभा सीटों से वंचित करने से प्रेरित है। अब मई, 2024 के बाद की टक्कर लिखने की कोशिश हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय सब कुछ ठाक नहा है। मई, 2024 के बाद कांग्रेस और पार्टी को खारिज नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार के इस पालाबदल से जहां विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। हालांकि हिंदी पट्टी में भाजपा की स्थिति मजबूत है, पर पार्टी किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती थी। इसलिए नीतीश को अपने पाले में लाकर उसने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'झड़िया' गठबंधन की जो थोड़ी भी संभावना थी, उसे ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा, भाजपा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह एक और राज्य में सत्ता में साझेदार बन गई है और जदयू के लिए राहत की बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसके नेता नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। जब-जब भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसके नतीजे अच्छे ही आए हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव था। भाजपा की रणनीति है कि विपक्षी गठबंधन की एकता को झटका देकर कैसे उसे लोकसभा सीटों से वंचित रखा जाए। पश्चिम बंगाल और पंजाब में पहले ही 'झड़िया' गठबंधन में दरार पैदा हो गई है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस और आप अभी झड़िया गठबंधन में बने हुए हैं। विपक्षी एकता के बारे में कहना जितना आसान है, उतना करना नहीं। अतीत में कई ऐसे मौके आए हैं, जब विभिन्न दलों एवं विचारधाराओं के लोग 1977, 1989, 1996, और 2004 में एकजट हए।

पलट के नीतीश एनडीए में

बीते बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ू के बीच करीब तीन घंटे की बैठक प्रधानमंत्री आवास में हुई थी। वह असामान्य बैठक थी। उनके सामने बिहार पर सर्वे की एक रपट भी थी, जो भाजपा ने कराया था। सर्वे का निष्कर्ष था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, अपने सभी घटक दलों समेत, 20-22 सीटें ही जीत सकती है। सर्वे अव्याध्या राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले कराया गया था। सर्वे में यह भी सामने आया कि उसके प्रभाव से 5-7 सीटें ही बढ़ सकती हैं। 2019 में भाजपा ने जद-यू के साथ 40 में से 39 सीटें जीती थीं। जाहिर है कि विरास्त का बिंदु बिहार और नीतीश कुमार रहे होंगे। अंततः यह तय हुआ कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का सूत्रधार ही पाला बदल कर भाजपा से मिल जाए, तो चुनावी फायदा हो सकता है। कमोविश अति पिछड़ा वर्ग के 'सरप्लस सोट' भी भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं। लंबे विरास्त के बाद प्रधानमंत्री ने नए गठबंधन को 'ओके' कह दिया। उसके बाद ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर 'पलटी' मार कर भाजपा से जुड़ेंगे। जो पटकथा लिखी गई थी, उसी के मद्देनजर नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। नीतीश ने मीडिया से पुष्टि की और कहा कि गठबंधन में काम नहीं हो पा रहा था। यहां और वहां के लोगों को तकलीफ थी, लिहाजा हमने गठबंधन छोड़ दिया है। अब नया गठबंधन बन रहा है। आप खुद देखिएगा। बहरहाल रविवार को ही नीतीश कुमार का एनडीए मुख्यमंत्री के तीर पर सपथ ग्रहण करना महज औपचारिकता थी। उनके साथ भाजपा के दो उपमुख्यमंत्रियों ने भी सपथ ली है। सप्नाट बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य पूरा ही बदल गया और लालू यादव, कांगेस खेमा मूकदर्शक ही बने रहे। इस बार नीतीश का मोहरंग होने और पलटी मार कर एनडीए में लौटने में सिफर ढेढ़ साल लगा। नीतीश अगस्त, 2022 में भाजपा को छोड़ कर लालू यादव खेमे में गए थे। पलटी मारने की दलीलें नीतीश की वही रही हैं, जो 2022 और उससे पहले 2017 में थीं। आश्चर्य है कि भाजपा और राजद दोनों ही जद-यू को तोड़ने की साजिश रचती रहती हैं और नीतीश बार-बार उन्हें के साथ सरकार बनाते रहे हैं। दरअसल एक सवाल जनादेश, सरकार, पलटीमारा राजनीति और लोकतंत्र को लेकर है। गौरतलब है कि 1995 से नीतीश कुमार ने विधायक का चुनाव ही नहीं लड़ा है। वह लगातार विधान परिषद में रहे हैं। उनके दलों को भी बहुमत का जनादेश कभी भी नहीं मिला है। फिर भी वह 9 वें बार मुख्यमंत्री बने हैं। वह देश का राजनीतिक रिकॉर्ड है कि एक ही नेता ने, एक ही कार्यालय के दौरान, तीन-चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सवाल है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या आकर्षण है कि भाजपा और राजद दोनों ही उन्हें 'पलटी' मारने को समर्थन देते रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनवा देते हैं? क्या नीतीश बिहार के राजनीतिक समीकरणों की विवशता है कि बहुमत न होने के बावजूद वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं? क्या यह पलटीमारा राजनीति की अवसरवादिता नहीं है? मौजूदा जनादेश 2020 में भाजपा-जदयूको मिला था, क्योंकि दोनों ने साझा तौर पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद का घटनाक्रम देश के सामने है।

